यूनियन कार्बाइड के ज़हरीले कचरे का निपटान कौन करेगा ?

विकीलीक्स द्वारा जारी किये गये एक खुलासे में कहा गया है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का यह मानना था कि भोपाल गैस त्रासदी में डाउ केमिकल कंपनी की कोई देनदारी नहीं बनती है। अमेरिकी दूतावास द्वारा भेजे गये केबल के अनुसार मोंटेक सिंह अहलूवालिया और केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने भी यह स्वीकार किया है कि यूनियन कार्बाइड कारखाने के परिसर में फैले ज़हरीले रासायनिक कचरे की सफ़ाई की ज़िम्मेदारी डाउ केमिकल्स की नहीं है। उल्लेखनीय है कि यूनियन कार्बाइड कारखाने को अमेरिका के डाउ केमिकल्स ने खरीद लिया है और इस तरह वहां पड़े ज़हरीले रासायनिक कचरे को साफ़ कराने की ज़िम्मेवारी इसी कंपनी की बनती है। पर यह कंपनी इस खर्चे से बचना चाहती है और इसने अमेरिका के मंत्रियों व अधिकारियों से इसके लिए भारत सरकार पर दबाव बनाया था। उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में रसायन व उर्वरक मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर डाउ कंपनी की जवाबदेही तय करने का अनुरोध किया था। अमेरिका ने भारत सरकार पर यह दबाव डाला है कि मंत्रालय अपनी याचिका वापस ले ले, पर इस मामले में कई स्वयंसेवी संस्थायें सक्रिय हैं जो डाउ केमिकल्स को कचरे की सफ़ाई के लिए ज़िम्मेवार मानती हैं, इसलिए सरकार के लिए याचिका को वापस ले लेना आसान नहीं है। लेकिन अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत रोनेन सेन ने भारत-अमेरिका सीईओ फोरम की बैठक में कहा था कि भोपाल त्रासदी के लिए डाउ केमिकल्स ज़िम्मेदार नहीं है और भारत सरकार इस मामले को आगे नहीं बढ़ायेगी। वहीं, दूसरी तरफ़ अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि इस मामले के कारण भारत में निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विकीलीक्स के खुलासे से जाहिर होता है कि बुद्धदेव भट्टाचार्य ने अमेरिकी राजनयिक को यह सुझाव दिया था कि वह इस मामले को प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री के स्तर पर उठायें। वे चाहते थे कि डाउ केमिकल्स पश्चिम बंगाल में निवेश करे। इसलिए वे डाउ केमिकल्स की चरण-वंदना में लगे थे। वे इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं थे कि भोपाल गैस त्रासदी कितनी बड़ी त्रासदी थी जिसमें हज़ारों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और यूनियन कार्बाइड का मालिक एंडरसन कंपनी को डाउ के हाथों बेच कर सभी ज़िम्मेदारियों से मुक्त हो गया और अब डाउ भी वहां पड़े रासायनिक ज़हरीले कचरे को उठवाने के लिए तैयार नहीं है। जब भारत सरकार उससे ऐसा करने का निवेदन करती है तो कंपनी कहती है कि वह यहां निवेश नहीं करेगी और बस सरकार के हाथ-पांव फूल जाते हैं। भोपाल गैस त्रासदी से परिचित हर व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि यूनियन कार्बाइड में पड़ा हुआ रासायनिक कचरा कितना ख़तरनाक है और दो दशक से से भी ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी उसके निपटान की सुध नहीं ली गई है। यह कचरा लोगों के लिए जानलेवा है और फ़िलहाल इस कचरे का मालिक डाउ केमिकल्स है। यूनियन कार्बाइड तो लाखों लोगों की जान के साथ खेल कर डाउ केमिकल्स में बदल गया और अब डाउ केमिकल्स लोगों की जान के साथ खेलने को तैयार बैठा है। यह हास्यास्पद ही है कि अब सीबीआई यूनियन कार्बाइड के मालिक एंडरसन के प्रत्यर्पण की अनुमति चाहती है, लेकिन इस बात को कौन भूल सकता है कि दुनिया की इस सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना के बाद जब एंडरसन भारत आया था तो उसे गिरफ़्तार कर उस पर कानूनी कार्रवाई करने की जगह उसे वापस अमेरिका भागने का मौका सरकार ने ही दिया था। सरकार में किस स्तर पर उसे भारत से जाने की इजाजत दी गई, इसे एक रहस्य बना दिया गया। दुर्घटना के वक्त मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे, वे मर गये, पर उन्होंने इस बारे में उतना ही मुंह खोला जितना सोनिया ने कहा। वैसे जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, वह जानती है कि केंद्रीय सत्ता के मुखिया के इशारे के बगैर एंडरसन को देश छोड़ने की इजाजत नहीं दी गई होगी। बहरहाल, जब भोपाल गैस पीड़ितों एवं स्वयंसेवी संगठनों ने यूनियन कार्बाइड कारखाने में ज़हरीले कचरे के निपटान की बात उठाई और सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया तो भारत सरकार ने 2005 में इस दिशा में कुछ काम शुरू किया और इसके खर्चे के लिए डाउ केमिकल्स से 100 करोड़ रुपये मांगे, पर डाउ केमिकल्स ने पैसा देने से साफ़ इनकार कर दिया। साथ ही, डाउ केमिकल्स ने यह भी कहा कि वह तब तक भारत में निवेश नहीं करेगी जब तक उसे इस देनदारी से मुक्त नहीं कर दिया जाता। इस पर सरकार नरम पड़ गई, जबकि उसे देशहित में डाउ केमिकल्स को कारखाने में पड़े कचरे की सफ़ाई के लिए बाध्य करना चाहिए था और कंपनी द्वारा ज़हरीले कचरे का निपटान नहीं करने की स्थिति में उसकी पूंजी जब्त कर लेनी चाहिए थी। पर एक साम्राज्यपरस्त सरकार में इतनी हिम्मत कहां? अगर ऐसा होता तो वह क्या एंडरसन को देश से भागने देती? साम्राज्यपरस्त सरकार को तो अमेरिका की नाराजगी का डर हर समय सता रहा था और अभी भी सता रहा है, इसलिए वह कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। ठोस निर्णय लेना तो दूर की बात, विकीलीक्स के खुलासे से जाहिर हो गया है कि किस तरह यहां के सत्ताधारी डाउ केमिकल्स के पक्ष में हैं। भोपाल गैस कांड से हुई हज़ारों मौतों की उन्हें जरा भी परवाह नहीं है। डाउ केमिकल्स का ज़हरीला कचरा अब अगर हज़ारों लोगों के लिए जानलेवा साबित होता है तो उन्हें इसकी भी परवाह क्या होगी! उन्हें तो सिर्फ़ विदेशी पूंजीनिवेश की परवाह है ताकि उनके 'खाने-पीने' का धंधा अच्छा चलता रहे। कमीशनखोरी चलती रहे और विदेशी बैंकों में उनका काला धन जमा होता रहे। ग़रीब जनता मरती है तो मरे, उनका क्या जाता है? यह है हमारे शासकों का चरित्र जो पूरी तरह जनविरोधी हो चुका है। डाउ केमिकल्स को कचरे का निपटान करने के लिए अपनी गांठ से पैसे न खर्च करने पड़ें, इसके लिए राजनेताओं के साथ इस देश के शीर्षस्थ पूंजीपतियों में से एक रतन टाटा ने भी अभियान चलाया था। रतन टाटा भारत-अमेरिका सीइओ फोरम के सह अध्यक्ष हैं। इन्होंने डाउ केमिकल्स को कचरे की सफ़ाई की ज़िम्मेदारी से बचाने के लिए सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि वे समान विचारों वाले औद्योगिक घरानों से सहयोग लेकर कचरे के निपटान के लिए रकम जुटाने की व्यवस्था करेंगे। सरकार को तो पैसा चाहिए। पूंजीपति अगर पैसा देते हैं तो उसे क्या उज्र? आखिर उन्होंने भी जनता को लूट-लूट कर ही अरबों की दौलत बनाई है। अगर पूंजीपतियों ने पैसा नहीं दिया और सरकार पर ज़्यादा दबाव पड़ा तो वह अपने खजाने से ही 100-200 करोड़ खर्च कर देगी, उसके खजाने में भी जनता से ही लूटा हुआ पैसा है, पर वह अमेरिकी कंपनी को नाराज नहीं करेगी जो नापाम, एजेंट आरेंज और डाइऑक्सिन जैसे ज़हरीले रसायनों का उत्पादन कर दुनिया भर में कितने ही लोगों की जान ले चुकी है और पर्यावरण को गहरी क्षति पहुंचा चुकी है। डाउ केमिकल्स कंपनी इस देश में देशवासियों के लाभ के लिए तो पूंजीनिवेश करेगी नहीं, पूंजीनिवेश वह अपने लाभ के लिए करेगी और लाभ में से कुछ टुकड़े यहां के सत्ताधारियों की तरफ़ फेंक देगी ताकि वे अपनी दुम हिलाते रहें।

- प्रतिनिधि

पाठक मंच

मज़दूर मोर्चा का नया अंक मिला। यह जान कर आश्चर्य हुआ कि पूर्व जज निर्मल यादव अपने ऊपर लगे रिश्वतखोरी के आरोप को साज़िश बता रही हैं और अब राजनीति में आना चाहती हैं। राजनीति में इनके परिवार के सदस्य हैं और ये आसानी से राजनीति में आ सकती हैं। यह क्षेत्र ऐसा है जहां हर किस्म के भ्रष्ट लोगों को आसानी से जगह मिल जाती है। निर्मल यादव को भी राजनीति में ऊंची जगह मिलेगी। जहां तक जनता की 'सेवा' की बात है, इसे जनता को 'लूटने' की बात समझना चाहिए। आज हर राजनेता जनता को लूटने में लगा हुआ है चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। ईएसआई के मुद्दे पर आपने जो समाचार छापा है, उससे स्पष्ट तौर पर सरकार की मूर्खता सामने आती है। सरकार चाहे तो अभी भी अपनी मूर्खता छोड़ ईएसआई में कवर होने वाले राज्य के ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूरों और उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें मुहैया करा सकती है। जहां तक आरक्षण के लिए जाट आंदोलन का सवाल है तो इसका कोई औचित्य नहीं है। अगर जाटों को आरक्षण मिलता है तो सभी ऊंची जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए। फ़िर आरक्षण के लिए आंदोलन का जो तरीका जाटों ने अपनाया, वह सर्वथा अनुचित था, पर आश्चर्य की बात है कि सरकार ने जाटों के प्रोत्साहन दिया। जापान की हालत को देखते हुए यह बात सही कही गई है कि शांतिपूर्ण कार्यों के लिए भी परमाणु उर्जा ख़तरनाक है। हमें उर्जा के अन्य स्रोतों की तलाश करनी चाहिए। हमें जल और वायु से मिलने वाली उर्जा पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा कम से कम उर्जा की खपत वाले साधन अपनाने चाहिए। यह तभी संभव है जब उपभोक्तावाद को हतोत्साहित किया जाये। पर पूंजीवादी व्यवस्था में उपभोक्तावाद निरंतर बढ़ता ही चला जाता है और अनावश्यक वस्तुओं को अति आवश्यक बना कर पेश किया जाता है। अरब जगत में जो भूचाल आया है, उस पर एजाज अहमद का लेख विचारणीय है। वैसे, अगले अंकों में आप इनके लेख के अन्य अंशों को छापेंगे, पर इसे पढ़ने से ही इनकी विचार-दिशा स्पष्ट हो जाती है। अरब जगत ही क्या, दुनिया के किसी भी देश की मुक्ति अब तथाकथित लोकतांत्रिक ढांचे में संभव नहीं है। अब साम्राज्यवाद से निर्णायक युद्ध का समय आ गया है और मज़दूर वर्ग ही मानवता को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष दासता से मुक्त कर सकता है। राहुल सांकृत्यायन पर विष्णुचंद्र शर्मा का लेख बहुत अच्छा लगा। आज कम्युनिस्ट आंदोलन में लगे लोगों ने एक तरह से राहुल को भुला दिया है, पर यह सच है कि राहुल जैसा बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति युगों में ही जन्म लेता है। राहुल शोषित-पीड़ित जनता के साथ थे और उनका लेखन सर्वहारा को सदा प्रेरणा देता रहेगा। अंक में प्रकाशित अन्य लेख एवं समाचार भी स्तरीय हैं और कड़वी सच्चाइयों को सामने लाते हैं। इस पत्र के प्रकाशन के लिए आप बधाई के पात्र हैं।

- मनोरंजन सिंह, नयी दिल्ली

मज़दूर मोर्चा का नया अंक मिला। निर्मल यादव पर आपने जो छापा है, वह उसके मुंह पर तमाचा है। आज हर भ्रष्ट व्यक्ति राजनीति में ही अपने लिए सुरक्षित जगह तलाशता है। शर्म नहीं आती निर्मल यादव को कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गईं, फ़िर भी कहती हैं कि उनके साथ साज़िश की गई ताकि वे सुप्रीम कोर्ट की जज न बन सकें। वैसे वे सुप्रीम कोर्ट की भी जज बन जातीं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्ट जज नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक से बढ़ कर एक भ्रष्ट जज रहे हैं और मुख्य जज रहे हैं। अभी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बालाकृष्णन भी भ्रष्टाचार की मूर्ति थे। ईएसआई पर आपने जो लिखा है, सही लिखा है, पर सरकार चलाने वालों को इतनी फुर्सत कहां कि वे जनता के हित की बात सोच सकें। वे तो हर समय जनता को लूटने की नयी-नयी योजनायें बनाने में व्यस्त रहते हैं। अगर जाटों को आरक्षण दिया जाता है तो फ़िर सबों को आरक्षण दिया जाये। संविधान में यह संशोधन कर दिया जाये कि हर जाति को आरक्षण मिलेगा, चाहे वह पिछड़ी हो या अगड़ी। परमाणु उर्जा का मामला बड़ा ही संवेदनशील है। जापान से पहले चेर्नोबिल में भी इसकी संहारक क्षमता देखी जा चुकी है। इसलिए इस उर्जा के प्रयोग पर बहस होनी चाहिए। राहुल पर लेख अच्छा लगा। एजाज अहमद का लेख पूरा पढ़ लूंगा तो उस पर टिप्पणी करूंगा। वैसे अरब जगत से तेल का दोहन साम्राज्यवाद का मुख्य लक्ष्य है और साम्राज्यवादी देश यही चाहेंगे कि उन देशों में भले ही तानाशाह शासक हों अथवा तथाकथित लोकजनतंत्रवादी, उन्हें तेल और गैस के दोहन की छूट मिलनी चाहिए। वैसे लीबिया पर हमले का मामला अति गंभीर है, लेकिन इसका विरोध शायद ही कोई देश कर रहा है। यानी अमेरिकी साम्राज्यवाद के आगे सभी देश नतमस्तक हैं। जहां तक विकीलीक्स द्वारा किये जाने वाले खुलासे की बात है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। सभी जानते हैं कि देश के सांसद बिकाऊ माल हैं। अंक में प्रकाशित नागार्जुन की कवितायें काफ़ी अच्छी लगीं। साहित्य के नाम पर आप सिर्फ़ कविताओं का ही प्रकाशन करते हैं, कभी कोई कहानी भी छापिये। इससे एकरसता भंग होगी। अंतिम पृष्ठ पर प्रकाशित समाचार 'थाने-चौकियां नीलाम होंगे तो अपराध नियंत्रित नहीं हो सकता' सही है, पर यह भी सही है कि वर्तमान व्यवस्था में थाने-चौकियों को नीलाम होने से कोई रोक नहीं सकता।

- नवीन चंद्र, फ़रीदाबाद

मज़दूर मोर्चा का अंक पढ़ने को मिला। इसमें प्रकाशित सभी सामग्री काफ़ी स्तरीय है और यह कोई साधारण समाचार-पत्र नहीं है। चाहे भ्रष्ट जज पर आपने लिखा हो या ईएसआई पर, जाट आंदोलन पर लिखा हो या परमाणु उर्जा के प्रयोग को लेकर, सबमें एक नयी दृष्टि दिखाई पड़ती है। राहुल सांकृत्यायन पर विष्णुचंद्र शर्मा का लेख काफ़ी पसंद आया। आज जरूरत है कि राहुल के साहित्य का प्रचार-प्रसार किया जाये। पर राहुल को कम्युनिस्टों ने उपेक्षित कर रखा है। इसकी वजह सिर्फ़ यह है कि वे सत्ता की चूहा-दौड़ में शामिल हैं। जहां तक अपने आप को क्रांतिकारी कहने वाले वाम संगठनों का सवाल है, वे बिखरे हुए हैं। छोटे-छोटे मुद्दों और नेतृत्व के सवाल को लेकर उनमें ठन जाती है और वे टूट-बिखर जाते हैं। इससे पता चलता है कि उनमें दूर-दृष्टि का अभाव है। कुछ संगठन ऐसे हैं जो ईमानदारीपूर्वक अपने काम में लगे हैं और संगठन बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं, पर उनके पास समर्पित कार्यकर्ताओं और संसाधनों का अभाव है। रह गये नक्सलवादी अथवा माओवादी। ये जब तक इस बात को नहीं समझेंगे कि पहाड़ों और जंगलों से निकल कर व्यापक मज़दूर आबादी तक उनकी पहुंच नहीं होगी, तब तक समाजवादी क्रांति की दिशा में कुछ खास नहीं हो सकता। आपके समाचार-पत्र में लगातार काफ़ी महत्त्वपूर्ण सामग्री छपती है, पर आप मज़दूर आंदोलन को लेकर एक बहस चलायें तो मेरी दृष्टि में उसका महत्त्व कुछ ज़्यादा होगा। इस बात को भूला नहीं जा सकता कि तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद पूंजीवाद-साम्राज्यवाद अभी मजबूत हुआ है और दुनिया के ग़रीब एवं विकासशील कहे जाने वाले देशों पर उसका दबदबा बढ़ा है। इस परिघटना की समीचीन व्याख्या होनी चाहिए। इस दिशा में मज़दूर मोर्चा को वामपंथी विचारकों, विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं से विचार-विनिमय करने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि इस व्यवस्था में संसद नीलाम होने की स्थिति में आ गई है तो थाने-चौकियों को कौन पूछने वाला है।

- रामनाथ वर्मा, फ़रीदाबाद

मज़दूर मोर्चा का अंक पहली बार एक मित्र के यहां पढ़ने को मिला। अपने घर लाकर जब इत्मीनान से मैंने इस अख़बार को पढ़ा तो आश्चर्यचकित रह गया कि अपने शहर से भी इतना स्तरीय प्रकाशन होता है। मुझे इस अंक में प्रकाशित सभी सामग्री अच्छी लगी। सारे समाचार एवं लेखों में नयी बात ही दिखाई पड़ती है जो अन्य किसी अख़बार में दुर्लभ है। इस अंक में लीबिया पर प्रकाशित लेख मुझे काफ़ी अच्छे लगे। इन लेखों से पता चलता है कि साम्राज्यवाद अभी भी ताकतवर स्थिति में है। राहुल सांकृत्यायन पर लेख भी काफ़ी अच्छा है। परमाणु उर्जा के उपयोग को लेकर जो लेख प्रकाशित किया गया है, वह भी विचारणीय है। नागार्जुन की कवितायें अच्छी लगीं। कुछ और जनकवियों की कवितायें प्रकाशित करें। आजकल तो जो कवितायें लिखी जा रही हैं, समझ में ही नहीं आतीं। शायद साहित्य का स्तर ऊंचा हो गया है। अब मैं इस अख़बार का नियमित पाठक बन जाऊंगा।

- पंकज पाराशर, फरीदाबाद